498 अंक लाकर 24 बच्चे दूसरे स्थान पर हैं। बारहवीं की एक टॉपर, आर्ट्स स्ट्रीम की हंसिका ने इंग्लिश में 99 मार्क्स को अपने साथ नाइंसाफी बताते हुए अदालत जाने की बात कही है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकॉलजी और हिंदुस्तानी वोकल (संगीत) में उसने 100 में से 100 हासिल किए हैं। क्या ये विषय ऐसे हैं जिनमें हर सवाल के सौ टंच सही जवाब दिए जा सकें? लगभग हर विषय में पूर्णांक पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का लगातार बढ़ना यही बताता है कि हमारी परीक्षा पद्धति मीडियॉक्रिटी के एक ढर्रे में फंसकर रह गई है।

खोखला नंबर गेम

संपादकीय

E-mail: jantaserishta@gmail.com

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की परीक्षाओं में साल दर साल नंबरों की मूसलाधार बारिश हमारी शिक्षा पद्धति को हंसी का पात्र बना रही है। इससे सीधा संकेत यह मिल रहा है शिक्षा में देर से सही, पर परीक्षा प्रणाली में तुरंत किसी बड़े बदलाव की जरूरत है। इस साल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 500 में 499 नंबर लाने वाले दो टॉपरों और 2 लाख 40 हजार से ज्यादा 90 पर्सेंट से ज्यादा मार्क्स लाने वालों के बाद 10वीं के बोर्ड में 13 बच्चों ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। इन सभी को 500 में से 499 अंक मिले हैं। 498 अंक लाकर 24 बच्चे दूसरे स्थान पर हैं। बारहवीं की एक टॉपर, आर्ट्स स्ट्रीम की हंसिका ने इंग्लिश में 99 मार्क्स को अपने साथ नाइंसाफी बताते हुए अदालत जाने की बात कही है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकॉलजी और हिंदुस्तानी वोकल (संगीत) में उसने 100 में से 100 हासिल किए हैं। क्या ये विषय ऐसे हैं जिनमें हर सवाल के सौ टंच सही जवाब दिए जा सकें? लगभग हर विषय में पूर्णांक पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या का लगातार बढ़ना यही बताता है कि हमारी परीक्षा पद्धति मीडियॉक्रिटी के एक ढर्रे में फंसकर रह गई है। तमाम स्कूल और कोचिंग संस्थान बच्चों को सिर्फ वह ढर्रा पकड़ाने के लिए, बच्चों को वह कुंजी थमाने के लिए बैठे हैं, जिससे अंकों का खजाना खुलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वे बच्चों को रट्टू तोता बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अंक बच्चों और उनके मां-बाप को तात्कालिक खुशी देते हैं और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन का रास्ता खोलते हैं। उनके भीतर रचनात्मकता को बढ़ावा देना इनके अजेंडे में ही नहीं है। बच्चों में उत्सुकता, जिज्ञासा, खोजबीन की तड़प या किसी कौशल में असाधारण निपुणता पैदा करना तो अब शिक्षण जगत की कल्पना से भी परे हो गया है। कुल मिलाकर इससे देश में धंधेबाजों और पिछलग्गुओं की जमात पैदा हो रही है। शोध और अन्वेषण में भारत के फिसड्डी रह जाने की मुख्य वजह यही है। वरिष्ठ भारतीय उद्यमी और बहुराष्ट्रीय कंपनियां शिकायत करती हैं कि भारत में इंजीनियरों के पास सिर्फ डिग्री होती है, योग्यता नहीं। हमारे शिक्षा ढांचे के पालनहारों को जवाब में कुछ कहना जरूरी नहीं लगता। भारत को नॉलेज पॉवर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना क्या इस पूर्णांक बांटने वाली शिक्षा पद्धति के बूते की बात है? परीक्षा के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन और देशों में भी किया जाता है लेकिन उनका जोर विद्यार्थियों की प्रतिभा को उभारने पर होता है। चीन में माओ त्से तुंग ने काफी पहले कहा था कि अगर पांच प्रश्नों में से पांचों के जवाब कोई औसत ढंग से दे तो उसे 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक न मिलें, लेकिन कोई छात्र यदि एक ही प्रश्न का असाधारण और मौलिक उत्तर दे तो भी उसे 60 प्रतिशत अंक दे दिए जाने चाहिए।

नक्सलवादियों पर भी हो सर्जिकल स्ट्राइक

लेख

-ललित गर्ग

नक्सल विरोधी अभियान 'ग्रीनहंट' को काफी सफलता मिली थी। यह 2009 में चलाया गया था जिसमें पैरामिलिट्री के जवान और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल थे। संयुक्त अभियान ने छत्तीसग?, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में फैले नक्सलियों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऑपरेशन 'प्रहार' वर्ष 2017 में छत्तीसग? के सुकमा जिले में चलाया गया था। इस अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, छत्तीसग? पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड व इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स के विशेष दस्ते शामिल थे। वक्त की जरूरत ऐसे ही अभियानों की तरफ इशारा करती है। जब तक इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा, इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी करने की जरूरत है।

नक्सलियों ने बीते सप्ताह गड़चिरौली में सुनियोजित हमले में 15 जवानों की हत्या करके यह संदेश दिया है कि उनका प्रभाव अभी बरकरार है। इस बड़े हमले से पहले भी एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हुईं जो इन कागजी दावों की पोल खोल रही थीं कि नक्सलवाद पर काबू पा लिया गया है। आखिर नक्सल समस्या की जड़ में क्या है और क्यों इस पर काबू पाने में किसी सरकार को कामयाबी नहीं मिल पा रही? ऐसे ही सवालों पर रमेश ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह से लंबी बातचीत की। प्रस्तुत हैं बातचीत के मुख्य अंश :

सवाल : सरकारें अक्सर नक्सलवाद पर काबू पाने के दावे करती हैं, लेकिन नक्सलवादी बीच-बीच में ऐसे हमले कर देते हैं जिनसे ये दावे खोखले साबित हो जाते हैं। आखिर चूक कहां हो रही है?

ऐसा सोचना हमारी बड़ी भूल होगी कि हमने नक्सल समस्या पर काबू पा लिया। नक्सली ब? मौकों की फिराक में रहते हैं। मौका मिलते ही अपने मंसूबे पूरे करने की कोशिश करते हैं। 2012 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने नक्सलियों से निपटने के लिए एक कार्ययोजना बनाई थी। नक्सल प्रभावित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर, आंतरिक सुरक्षा की विस्तृत योजना तैयार की गई थी। उसके बाद से कोई योजना नहीं बनी। नई सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि बाहरी सुरक्षा के बजाय हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। कई सालों से राज्यों में पुलिस फोर्स और पुलिस स्टेशनों की भारी कमी है। सुरक्षाकर्मियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स?कें जर्जर स्थिति में हैं। इन सबका फायदा नक्सली उठा रहे हैं।

सवाल : इन मोर्चों पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है?

दरअसल कुछ वर्षों से हमारा सुरक्षातंत्र नक्सलियों को हल्के में लेने लगा है जिसका वे फायदा उठा रहे हैं। नक्सलियों से ल?ने के लिए ठोस नीति बनाए जाने की दरकार है। इनके कुचक्र को भेदने के लिए विशेष दस्ते की जरूरत है। सात-आठ वर्ष पूर्व केंद्र और राज्यों ने मिलकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो विशेष विकास योजना तैयार की थी, वह उन क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की कम मौजूदगी या गैर मौजूदगी की वजह से लागू नहीं हो पाई थी। कम से कम अब उसे सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

सवाल : नक्सल समस्या के मूल में क्या है? आखिर क्यों ये लोग अपनों का खून बहा रहे हैं?

हिंदुस्तान में जब सबसे पहले नक्सलियों ने दस्तक दी थी, तो उस वक्त मेरा इनसे सीधे मुकाबला हुआ था। इनकी एक चाहत रही है कि अगले पचास वर्षों में ये लोग अपनी हुकूमत भारत पर कायम करें। हालांकि उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये वे पिछड़े लोग हैं जो विकास की मुख्यधारा से कभी जुड़ नहीं पाए। इनको लगता है, सरकारों ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। मैंने देखा था जब कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूछताछ में यही बताया कि वह भी औरों की तरह देश के भागीदार बनना चाहते थे, लेकिन उनको दरकिनार किया गया और मजबूरी में उन्हें हथियार उठाना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने एक के बाद एक हिंसक घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया तो उनके और सरकार के बीच चौड़ी खाई बन गई। सरकार की नजरों में आज ये आतंकवादी हैं। इनके कृत्य ही कुछ ऐसे हैं।

सवाल: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2014 में कहा था कि नक्सली भटके हुए हमारे भाई हैं। इनको सही रास्ते पर लाएंगे। उनकी भावनात्मक अपील का भी कोई असर नहीं हुआ।

असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नक्सली तब तक बहुत आगे निकल चुके थे। उनको पता था कि अगर एक बार सरकार के चंगुल में फंस गए तो उनकी खैर नहीं। इस वक्त कई नक्सली संगठन बन चुके हैं। कुछ सही रास्तों पर आ भी गए हैं। लेकिन ज्यादातर संगठन अब भी छद्म लड़ाई में ही विश्वास कर रहे हैं। नक्सलवाद के विचारधारात्मक विचलन की सबसे बड़ी मार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, झारखंड और बिहार को झेलनी प? रही है। अब इनकी शाखाएं धीरे-धीरे दूसरे जगहों पर भी फैलनी शुरू हो गई हैं। सचाई यह है कि हिंदुस्तान में नक्सलियों के समर्थकों की संख्या कम नहीं है। हालांकि कोई खुलकर उनका समर्थन नहीं करता।

सवाल: नक्सलियों से निपटने के लिए दो बड़े अभियान 'ग्रीनहंट' और 'प्रहार' चलाए गए थे। आपको नहीं लगता कि कुछ और अभियानों की जरूरत है?

नक्सल विरोधी अभियान 'ग्रीनहंट' को काफी सफलता मिली थी। यह 2009 में चलाया गया था जिसमें पैरामिलिट्री के जवान और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल थे। संयुक्त अभियान ने छत्तीसग?, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में फैले नक्सलियों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऑपरेशन 'प्रहार' वर्ष 2017 में छत्तीसग? के सुकमा जिले में चलाया गया था। इस अभियान में सीआरपीएफ, कोबरा कमांडो, छत्तीसग? पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड व इंडियन एयरफोर्स के एंटी नक्सल टास्क फोर्स के विशेष दस्ते शामिल थे। वक्त की जरूरत ऐसे ही अभियानों की तरफ इशारा करती है। जब तक इनके साथ सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा, इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी करने की जरूरत है। समय रहते अगर इनके नापाक मंसूबों को नहीं रोका गया तो गड़चिरोली जैसी आंखमिचौली नक्सली आगे भी खेलते रहेंगे।

चिंतन कण

छूटने का भय

हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि हम कौन हैं? क्योंकि अभी तक हम अपने को जिस रूप में जानते हैं वह सही नहीं है। सृष्टि की संरचना और इसमें आने वाले जीव के विषय में जो विचार करते हैं, उनका कहना है कि जैसे ही जीव इस धरती पर कदम रखता है, पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों, एक मन और एक बुद्धि से युक्त इसका शरीर भी इसके साथ-साथ चला आता है। हालांकि यह शरीर इसके साथ तो आता है, किंतु यह इसका अपना इसलिए नहीं होता, क्योंकि यह जीव तो उस परब्रह्म परमात्मा का अंश है, जो जन्म और मरण से मुक्त है और जिसमें सुख-दुख की व्याप्ति नहीं होती। जीव को कब कौन-सा शरीर मिलेगा और कब कौन-सा शरीर उससे छूट जाएगा, इसका न तो इसे पता होता है और न ही अपना शरीर प्राप्त करना तथा छोड़ना इसके वश में होता है, क्योंकि न तो यह अपने शरीर का स्वामी है और न यह शरीर इसका अपना है। इसलिए इसके छूटने का भय निरर्थक है।

यही स्थिति सांसारिक संबंधों की भी है। इस जीव ने जिस किसी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया वही इसकी माता हो गई। जिस किसी पुरुष ने इसका पालन-पोषण किया उसे पिता कहा जाने लगा। जो इसकी माता के ही गर्भ से जन्मे वे भाई-बहन हो गए। इसी तरह से सांसारिक संबंधों का एक ब?ा जाल बिछ गया, जिसका जु?ाव समाज और राष्ट्र से हो गया, किंतु यथार्थ फिर वही है कि इनमें से इस जातक का अपना इसलिए कोई नहीं है, क्योंकि जिस मां के गर्भ से इसका जन्म हुआ, जिस पिता ने पालन-पोषण किया और एक ही गर्भ से जन्म लेने के कारण, जो इसके भाई-बहन बने, क्या वे सभी पूर्व जन्म में इसके साथ थे? कब तक साथ रहेंगे और क्या अगले जन्म में भी इसे मिलेंगे? इसका कोई ठिकाना इसीलिए नहीं है, क्योंकि यथार्थ में इसका अपना कोई है ही नहीं। यही स्थिति इसकेजीवन में प्राप्त होने वाली भोग-सामग्री की भी है। मकान, दुकान, पद-प्रतिष्ठा, लाभ-हानि के होने न होने का क्या कोई ठिकाना है? सब कुछ अनिश्चय है, क्योंकि इन सबसे भी जीव का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसीलिए जब इसका कुछ है ही नहीं, तब फिर कुछ भी छूट जाने का भय निरर्थक है।

-डॉ. गदाधर त्रिपाठी

नाक की सीद में चलने का और नॉन इशू पे बात नई करने का

अपुन कू तो बावा, यईच लगता है, बोले तो भोत बड़ा हो गएला है अपुन का मुलुक, पांच बरस में भोत जास्ती बदल गएला है इसका आउटलुक। अबी तलक जो था चिरकुट भाप का इंजिन का माफिक छुक छुक, वोईच अक्खे वर्ल्ड में चला रएला है बुलेट ट्रेन का माफिक भाईगीरी का चाबुक। टाइम अबी है थोड़ा नाजुक तो कोल्ड स्टोरेज में रखने का अबी पब्लिक का सुख-दुख और ये बी नई पूछने का, बोले तो कायकू फ्लॉप हो रएला है किंग खान शारुख! बोलने का मतलब यईच है, बोले तो नाक की सीद में चलने का और नॉन इशू पे बात नई करने का।

> टाइम अबी है थोड़ा नाजुक तो कोल्ड स्टोरेज में रखने का अबी पब्लिक का सुख-दुख और ये बी नई पूछने का, बोले तो कायकू फ्लॉप हो रएला है किंग खान शारुख! बोलने का मतलब यईच है, बोले तो नाक की सीद में चलने का और नॉन इशू पे बात नई करने का। क्या है ना भाय, बोले तो अबी अपुन के मोटा भाई का नाम चलता है तो हर कोई मोटा भाई का नाम से जलता है।

क्या है ना भाय, बोले तो अबी अपुन के मोटा भाई का नाम चलता है तो हर कोई मोटा भाई का नाम से जलता है। मोटा भाई का देखना है एकदम कड़क कारनामा, तो देखने का वो ओबामा, बोले तो मोटा भाई का सामने लगता है एकदम सुदामा। तू तड़ाक से 'क्या रे' बोल के करता है जिगरी दोस्ती का ड्रामा। मोटा भाई की डिप्लोमेसी बोले तो कातिल हसीना, बोले तो वो हटेले मुलुक चाइना कू बी आ जाता है पसीना। अबी देखे ना भाय, खिल्ला ठोक के टेररिज्म के ताबूत पे, चुनाव का टाइम पे कैसा वो मसूद कू पक? के बिठा दिया बूथ पे और वो ट्रम्प तो मोटा भाई का सामने हो जाता है स्टंप्ड, बोले तो दिमाग कू हिला देता है मोटा भाई के नाम का भूकंप।

अपुन तो क्या है ना भाय, इत्ता बी नई है भोला और अपुन कू जो सामने सीदा सच्चा दिखा, वोईच बोला। पन अपुन का यार सलीम पानी एकदम पकेला राइस है, बोले तो है एक ईच, पन दो पे दो बावीस है। वो बोलने कू लगा, 'अबे ढक्कन, तू कबी समजेंगा और तेरे मगज के प्लेयर में ये एक ईच गाना कबी तलक बजेंगा! किदर कुच नई बदलेला है, इदर वोईच सांप सपेरे का खेला है। पएला हर बात में होता था विकास, अबी किसकू बी नई मांगता है विकास। विकास की छील के रख दिएले हैं घास, बोले तो सब बकवास।'

अबी पानी बीएमसी की फुटेली पाइप लाइन से उड़ता हुआ फुव्वारा है और उसकी हर बात में एक इशारा है। वो बोलने कू लगा, 'तू देख ले खजूर, वोट मांगने का टाइम पे कायदे की सब बात एक साइड और बाकी सब कार्बन डाई ऑक्साइड, बोले तो हर दावा बिगेर जांचा और हर बात में लोचा लबाचा। अपुन के इदर तो कोई पार्टी बी होने कू होती है ग्रीन वायरस, बोले तो डेमोक्रेसी की चिलम में मजहब की चरस। किदर वोटर के मगज में मचती है खलबली, तो लीडर लोक याद दिला देते हैं हजरत अली और बजरंग बली, बोले तो तोड़ दुश्मन की नली, कायकू बोले तो रियल इशू पे जास्ती सोचने का नई और पक?ने का पतली गल्ली। अबी अपुन के इदर तो हालत ये है, बोले तो एक पार्टी के लीडर कू पड़ता है लाफा, तो दूसरी पार्टी कू नजर आने कू लगता है मुनाफा, बोले तो दो चार सीट का इजाफा।'

-अवधेश व्यास

कटाक्ष

इनकी जुबां

बीजेपी की कोई भी महिला नेता अपने पति को मोदी के पास नहीं भेजती।

- मायावती
बसपा सुप्रीमो

हरियाणवी सॉन्ग 'गोली चल जावेगी' पर जमकर ठुमके लगा रही हैं। वहीं वहां मौजूद लोग उनका डांस करते हूटिंग कर रहे हैं।

सपना चौधरी
अभिनेत्री

प्रधानमंत्री पर मायावती का बयान शर्मनाक।

-निर्मला सीतारमण
केंदीय रक्षा मंत्री

जन-मंच

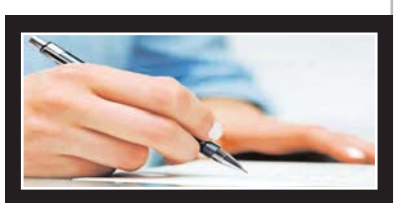

आरोपों का चुनाव

चुनाव में एक-दूसरे को कमतर बताने के आरोपों के बीच जनता के अहम मुद्दे गुम हो गए हैं। कोई भी दल उन मुद्दों पर बात नहीं कर रहा, जो इन चुनावों में उठने चाहिए थे। जैसे, अगर वे सत्ता में आएंगे, तो किस तरह की शिक्षा नीति बनाएंगे, कैसे हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएंगे, रोजगार के लिए उनकी नीति क्या होगी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वे किस तरह से प्रभावी कदम उठाएंगे? इन सबको छोड़कर बहस इस बात पर हो रही है कि मेरी कमीज से ज्यादा तुम्हारी कमीज गंदी है। दाग मेरे दामन से ज्यादा तुम्हारे दामन पर हैं। मगर असल मुद्दों पर खुद का दृष्टिकोण बताने की जरूरत कोई नहीं समझता। चुनाव तो पूरी तरह से स्तरहीन आरोपों तक सिमट गया है। क्या राजनीतिक दल जनता के सवालों के घेरे में आने से बचने के लिए चुनाव में असल मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं? जाहिर है, मतदाताओं को ही सोचना-समझना होगा कि इन आरोपों की असल हकीकत क्या है? असल मुद्दों को दरकिनार करने का यह चलन कल के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक है।.

-**युधिष्ठिर लाल कक्कड़,** भिलाई

गिरती नैतिकता

पिछले कुछ वर्षों में देश के कर्णधारों और नेताओं में अनुशासन की कमी के साथ-साथ नैतिकता भी गिरी है। यह जनहित व देशहित में ठीक नहीं है। किसी की जुबान फिसलकर भ्रम फैला रही है, तो किसी पर करोड़ों रुपये में टिकट बेचने का आरोप लग रहा है। कोई प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खिलवा? कर रहा है, तो कोई इतनी निम्न-स्तरीय भाषा का प्रयोग कर रहा है कि उसे बयां करना भी अशोभनीय है। इन सबमें जनता के मूल मुद्दों को हवा में उड़ा दिया गया है और व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक सारा मसला सिमट गया है। जिनका अपनी जुबान पर लगाम नहीं, जिनके आचार-विचार ठीक नहीं, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और जिनकी नैतिकता खत्म हो गई है, उनसे भला यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे मतदाताओं को सुशासन देंगे और उन्हें सही दिशा प्रदान करेंगे।.

-**महेश नेनावा,** अंबिकापुर

अनिवार्य हो मतदान

लोकसभा चुनाव छठे चरण को भी पार कर गया। फिर भी, हमारे आसपास काफी संख्या में ऐसे लोग मिलते हैं, जो आने वाली सरकार से उम्मीदें तो ढेर सारी लगाकर बैठे हैं, परंतु वे मतदान करने नहीं गए। वोट देना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। यह जानते हुए भी कि मतदान और लोकतंत्र के बीच परस्पर संबंध है, लोगों को ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुमकिन हो, तो वोट देना अनिवार्य बना देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश वोट नहीं दे पाता है, तो उससे कारण पूछा जाना चाहिए और उत्तर संतोषजनक न पाए जाने पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सबको यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र की सफलता मतदाताओं की जागरूकता पर ही निर्भर है। अगर मतदाता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तो उन्हें मजबूर किया ही जाना चाहिए।.

-**करुणा सिंह,** राजनांदगांव

विकृत मानसिकता

एक महिला अधिकारी की तस्वीर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। कहा जा रहा है कि वह महिला लखनऊ में चुनाव करवाने पहुंची हैं। उनके हाथ में ईवीएम भी साफ-साफ नजर आता है। मगर दुख तब होता है, जब कुछ लोग उन्हें ब?ी अभद्रता से देखते हैं। वे तो यह भी कहने से नहीं चूकते कि चुनाव आयोग को करो?ं रुपये मतदाता जागरूकता के नाम पर यूं ही खर्च करने की जगह ऐसी महिलाओं को पोलिंग बूथ पर भेजना चाहिए। ऐसी भद्दी सोच से मन क्षुब्ध हो उठता है। जब समाज के लोगों की ऐसी सोच होगी, तो महिलाएं खुद के सुरक्षित होने की आखिर कल्पना भी कैसे कर सकेंगी?.

-**स्वालिहा,** रायपुर

बजट से उम्मीदें

मोदी सरकार का यह आखिरी बजट है। हालांकि इसे हम पूर्ण बजट नहीं कह सकते, यह अंतरिम बजट ही है, फिर भी यह देश की अर्थव्यवस्था की सूरत और आगामी योजनाओं की एक झलक तो पेश करेगा ही। चूंकि आम चुनाव नजदीक हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि सरकार कुछ लोक-लुभावन घोषणाएं भी करेगी। लेकिन हम मध्यवर्गीय नौकरीशुदा लोग तो बस टैक्स में कुछ रियायतों की अपेक्षा करते हैं, ताकि जिंदगी कुछ आसान बसर हो। उम्मीद है कि सरकार इस बार टैक्स छूट का दायरा पांच लाख तक करेगी। वैसे भी, जब सरकार यह मानती है कि आठ लाख रुपये सालाना आय वाले लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनकी संतानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, तो फिर उन पर टैक्स का भार भी नहीं डालना चाहिए। जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं महंगी होती जा रही हैं और इनमें सरकारी हिस्सेदारी कम होती जा रही है, उसे देखते हुए गरीबों- मध्यवर्ग के हितों का बजट में खास ख्याल किया जाना चाहिए। आशा है, सरकार हमारी हालत समझेगी।.

-**अधीर शर्मा,** बिलासपुर